

ईरान परमाणु समझौता

प्रलिस के लयि:

संयुक्त वयापक कार्य योजना, ईरान और आसपास के देश ।

मेन्स के लयि:

भारत के हतियों को प्रभावति करने वाले भारत से जुड़े समूह और समझौते, JCPOA और इसका महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

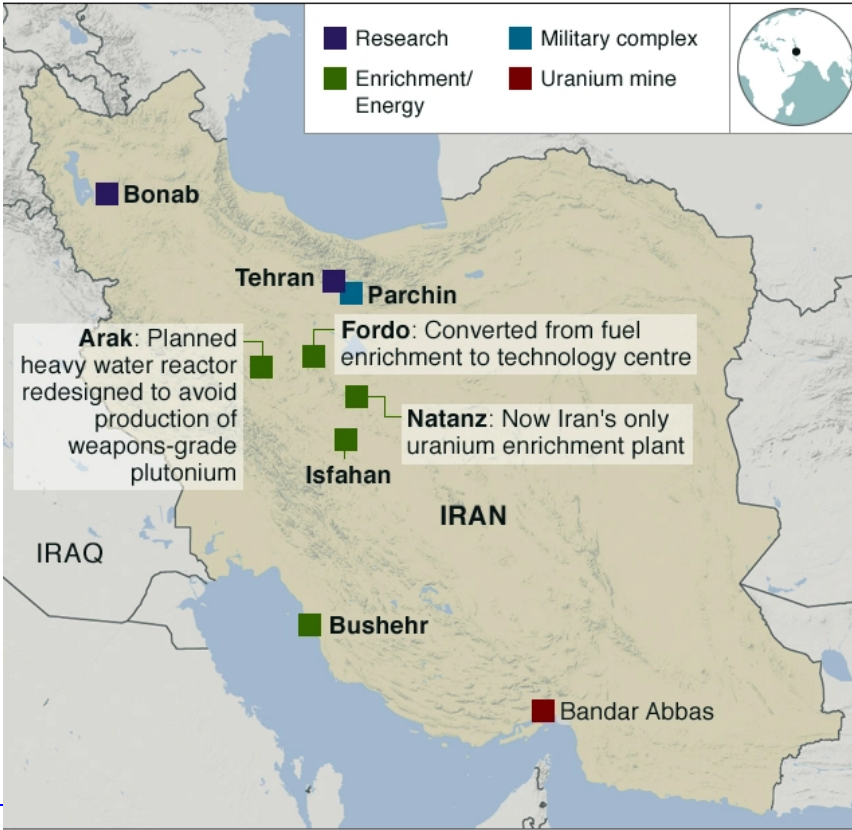
हाल ही में ईरान (तेहरान) के वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवति करने हेतु एक समझौते की तलाश में ईरान तथा वशिव शक्तियों के राजनयकों ने वयिना (ऑस्ट्रिया) में फरि से मुलाकात की ।

- राष्ट्रपति बिराक ओबामा द्वारा हस्ताक्षरति ईरान परमाणु समझौता, 2015 को वर्ष 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समाप्त कर दया था ।
- अमेरिका ने कहा कअगर ईरान मूल समझौता शर्तों का अनुपालन करता है तथा बैलसिटिक मसिाइल भंडार और छद्म युद्ध से संबंधति अन्य मुद्दों को संबोधति करता है तो वह इस समझौते में फरि से शामिल हो सकता है ।

वर्ष 2015 का ईरान परमाणु समझौता:

- इस सौदे को औपचारिक रूप से संयुक्त वयापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है ।
- CPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ या EU) के बीच वर्ष 2013 एवं वर्ष 2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था ।
- ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के नरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकयिह सुनिश्चित हो सके कईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार वकिसति नहीं कर रहा है ।
- हालाँकपश्चिमि, ईरान के परमाणु प्रसार से संबंधति प्रतबंधों को हटाने के लयि सहमत हो गया है, जबकभानवाधकारों के कथति हनन और ईरान के बैलसिटिक मसिाइल कार्यक्रम को संबोधति करने वाले अन्य प्रतबंध यथावत रहेंगे ।
- अमेरिका ने तेल नरियात पर प्रतबंध हटाने के लयि प्रतबिद्धता व्यक्त की है, लेकिन वतितीय लेन-देन को प्रतबंधति करना जारी रखा है जसिसे ईरान का अंतरराष्ट्रीय वयापार बाधति हुआ है ।
- फलिहाल ईरान की अर्थव्यवस्था में मंदी, मुद्रा मूल्यहरास और मुद्रास्फीति के बाद समझौता प्रभावी होने से काफी स्थरिता आ गई है तथा इसके नरियात में वृद्धि हो रही है ।
- मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इज़रायल ने इस सौदे को वृद्धता से खारजि कर दया है और ईरान के महत्त्वपूर्ण कषेत्रीय प्रतदिवंदवी सऊदी अरब जैसे अन्य देशों ने शकियात की है कयि वार्ता में शामिल नहीं थे, हालाँकईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस कषेत्र के हर देश के लयि सुरक्षा ज़ोखमि पैदा कर दया है ।
- ट्रम्प द्वारा इस सौदे को छोड़ने, बैकगि तथा तेल प्रतबंधों को बहाल करने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा दया, जो वर्ष 2015 से पहले की उसकी परमाणु कषमता का लगभग 97% है ।

Changes agreed under Iran deal to limit nuclear programme



अमेरिका के समझौते से हटने के बाद:

- अप्रैल 2020 में अमेरिका ने प्रतर्बिंधों को वापस लेने के अपने इरादे की घोषणा की। हालाँकि अन्य साझेदारों ने इस कदम पर आपत्तजिताते हुए कहा कि अमेरिका अब इस सौदे का हिससा नहीं है, इसलिये वह एकतरफा प्रतर्बिंधों को फरि से लागू नहीं कर सकता है।
- प्रारंभ में वापसी के बाद कई देशों ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा दी गई छूट के तहत ईरान से तेल का आयात करना जारी रखा। एक साल बाद अमेरिका ने बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं के साथ इस छूट को समाप्त कर ईरान के तेल नरियात पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया।
- अन्य पक्षों ने सौदे को बनाए रखने के प्रयास में अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के बाहर ईरान के साथ लेन-देन की सुविधा हेतु 'INSTEX' के रूप में जानी जाने वाली एक वस्तु वनिमिय प्रणाली शुरू की। हालाँकि 'INSTEX' ने केवल भोजन एवं दवा को कवर किया, जो कि पहले से ही अमेरिकी प्रतर्बिंधों से मुक्त थे।
- जनवरी 2020 में अमेरिका द्वारा शीर्ष ईरानी जनरल कासमि सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने घोषणा की कि वह अब अपने यूरेनियम संवर्द्धन को सीमति नहीं करेगा।

JCPOA की बहाली संबंधी चुनौतियाँ:

- सऊदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्रीय शीत युद्ध इस बहाली में एक बड़ी बाधा है।
- अमेरिका और सऊदी अरब ने अमेरिका की मध्य पूर्व नीतिके अनुसार ईरान का मुकाबला करने के लिये अपने द्वपिक्षीय संबंधों को मज़बूत किया है।
- इन देशों के बीच पारंपरिक 'शयिया' बनाम 'सुन्नी' संघर्ष ने इस क्षेत्र में शांति हेतु वार्ता को मुश्किल बना दिया है।
- ईरान वर्तमान में अपनी कई प्रतर्बिद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें समृद्ध यूरेनियम के भंडार की सीमा का भी उल्लंघन शामिल है और यह जतिना अधिक होगा सौदा उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- ट्रंप प्रशासन के सौदे से पीछे हटने और पुनः प्रतर्बिंध लगाने के कारण ईरान अपने आर्थिक नुकसान के लिये अमेरिकी प्रतर्बिंधों को उत्तरदायी ठहरा रहा है।

भारत के लिये JCPOA का महत्त्व:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा:
 - ईरान पर लगे प्रतर्बिंधों के हटने से चाबहार, बंदर अब्बास बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य योजनाओं में भारत के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा।
 - यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थितिको बेअसर करने में भारत की मदद करेगा।

- चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुज़रने वाले 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे' (INSTC) से भारत के हितों को भी बढ़ावा मलि सकता है। गौरतलब है कि INSTC के माध्यम से पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

■ ऊर्जा सुरक्षा:

- अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल के आयात को शून्य करना है।
- अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने तथा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने में सहायता मल्लिगी।

आगे की राह

- अमेरिका को न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम बल्कि क्षेत्र में उसके बढ़ते शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। उसे नए बहुधुवीय विश्व की वास्तविकता को भी ध्यान में रखना होगा, जसिमें अब उसके एकतरफा नेतृत्व की गारंटी नहीं है।
- ईरान को मध्य पूर्व में तेज़ी से बदलती गतशीलता पर वचिार करना होगा, यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में इज़रायल ने कई मध्य पूर्वी अरब देशों के साथ अपने संबंधों को पुनर्गठित कयिा है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/iran-nuclear-deal-1>

